

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 08-09-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

सोमवार, 08 सितम्बर, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus :Prelims	ब्लडमून
Page 02 Syllabus :GS 1 : Modern History/ Prelims	तमिलनाडुमेंस्वाभिमानआंदोलन के 100 वर्षों पर नजर
Page 07 Syllabus :GS 3 : Science and Technology / Prelims	अंतरिक्षमेंखोगया? अपना रास्ता खोजने के लिए आपको सिर्फ दो सितारों की आवश्यकता हो सकती है
Page 08 Syllabus :GS 1 : Social Issues / Prelims	अनुग्रहकेसाथधूसर होना: बदलती जनसंख्या गतिशीलता के लिए सरकारों के लिए एक नीति पुनर्विन्यास की आवश्यकता होती है
Page 08 Syllabus :GS 3 : Disaster Management / Prelims	निकोबारमेंएकपारिस्थितिक आपदा का निर्माण
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus :GS 2 & 3 : Social Justice & Indian Economy	जीएसटी 2.0 युवाभारतीयों को सशक्त करेगा

Page 01 : प्रारंभिक परीक्षा

रविवार की रात, भुवनेश्वर सहित भारत में स्काईवॉचर्स ने एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी – कुल चंद्र ग्रहण, जिसे लोकप्रिय रूप से ब्लड मून के रूप में जाना जाता है। यह घटना तब हुई जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर गया, जिससे यह लाल रंग का हो गया। पूर्ण ग्रहण का चरण रात 11:01 बजे शुरू हुआ और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बड़े हिस्सों में दिखाई दिया।

Blood moon

Sky show: The blood moon atop Bhubaneswar during the lunar eclipse on Sunday. The total eclipse phase which began at 11.01 p.m. caught the attention of skywatchers across India and other nations. BISWARANJAN ROUT

प्रीलिम्स के लिए मुख्य विवरण

1. ब्लड मून क्या है?

- यह पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होता है, जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाली धूप बिखर जाती है।

- छोटी तरंग दैर्घ्य (नीला/हरा) बिखर जाती है, जबकि लंबी लाल तरंग दैर्घ्य चंद्रमा की ओर झुकती है, जिससे यह लाल रंग का रूप देता है।
- यह प्रभाव रेले स्कैटरिंग के कारण है - यही कारण है कि सूर्यास्त लाल दिखाई देता है।

2. खगोलीय महत्व

- सूर्य ग्रहण के विपरीत, चंद्र ग्रहण नग्न आंखों से देखने के लिए सुरक्षित हैं।
- यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करने में मदद करता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल के माध्यम से फ़िल्टर की गई सूरज की रोशनी चंद्रमा को पेंट करती है।

3. भौगोलिक कवरेज

- भारत (देर रात), दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में दिखाई देता है।
- भारत का पूरा देश कम से कम आंशिक चरण देख सकता है।

4. प्रीलिम्स पॉइंट्स

- सूर्य बनाम चंद्र ग्रहण → सूर्य ग्रहण अमावस्या पर होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर।
- आवृत्ति → 2-5 चंद्र ग्रहण हर साल होते हैं, लेकिन कुल ग्रहण दुर्लभ होते हैं।
- सूर्य - पृथ्वी - चंद्रमा → संरेखण (चंद्र ग्रहण के लिए)।

निष्कर्ष

हाल ही में ब्लडमून न केवल एक दृश्य तमाशा था, बल्कि खगोलीय पिंडों और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच गतिशील संबंधों का एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक भी था। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए, यह प्रकाश प्रकीर्णन, आकाशीय यांत्रिकी और ग्रहण दृश्यता के भूगोल की अवधारणाओं को पुष्ट करता है - ये सभी यूपीएससी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: ब्लड मून लाल दिखाई देता है क्योंकि:

- ग्रहण के दौरान चंद्रमा अपना लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है
- पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश की कम तरंगदैर्घ्य को प्रकीर्णित करता है, जबकि चंद्रमा तक अधिक लाल तरंगदैर्घ्य पहुँचता है
- सूर्य ग्रहण के दौरान केवल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है
- मंगल से परावर्तन चंद्रमा को उसका लाल रंग देता है

उत्तर: (b)

वर्ष 2025 तमिलनाडु में आत्म-सम्मान आंदोलन की शताब्दी का प्रतीक है, जिसका नेतृत्व पेरियार ईवी रामासामी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद किया था। आंदोलन ने जाति पदानुक्रम, पितृसत्तात्मक मानदंडों और धार्मिक रूढ़िवादिता पर सवाल उठाया, तमिल समाज को नया आकार दिया और द्रविड़ आंदोलन के लिए वैचारिक नींव रखी। इसकी शताब्दी भारत के सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रवचन में अपने योगदान को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती है।

Looking back at 100 years of the Self-Respect Movement in Tamil Nadu

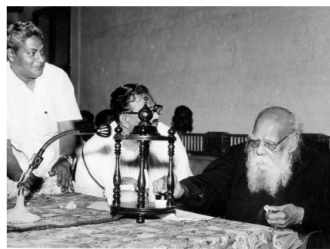
C. Palanivel Rajan
MADURAI

This year marks the centenary of the Self-Respect Movement, which changed the course of political discourse in Tamil Nadu. Though the movement was recorded to have started in 1925, historians contend that it did not have a singular moment of origin.

In their book, *Towards a Non-Brahmin Millennium* (From Iyothee Thass to Periyar), V. Geetha and S.V. Rajadurai write: "The Self-Respect Movement comes to us, as it were, in process, as an ideological impulse, an energetic mobilising of men and women across castes and classes, a vision of a society that had erupted into rebellion, into acts of defiance, daring and, finally, as a time of great churning, when all things

were subject to doubt and enquiry, when all matters, however sacred and inviolate were relentlessly interrogated...When women ignored the claims of family and the bonds of community; when young men willingly forsook personal fortunes and defied elders; a time when scores of hitherto despised and ignored peoples, until then, mere objects of charity, pity and paternalist benevolence, were asked to play protagonists in a struggle which, above all, was committed to running their world upside down." Social reformer Periyar E.V. Ramasamy, who later founded the Dravidar Kazhagam, through the launch of Tamil weekly *Kudi Arasu* (Republic), paved the way for the formal beginning of the Self-Respect Movement.

Following his departure



Leading light: Social reformer Periyar E.V. Ramasamy, through the launch of Tamil weekly *Kudi Arasu*, paved the way for the formal beginning of the Self-Respect Movement.



from the Indian National Congress in November 1925, Periyar utilised an opportunity to address a Justice Party special conference in Coimbatore "to espouse a radical and militant non-Brahminism".

According to the authors, "He observed that the Justice Party had been un-

able to attract popular support because it did not have a political programme which addressed the real needs of the people." He said its members and leaders seemed to labour under the illusion that an English education and a position in the services, in themselves,

would bring cheer and good to the non-Brahmin commonweal.

Radical reform

Periyar went on to assure his audience that he endorsed these objectives, but did not consider them a significant achievement in themselves.

"They could very well go to constitute a non-Brahmin elite which, in the days to come, could prove as oppressive as a Brahmin oligarchy," he warned.

Kudi Arasu was seen as an extension of the Self-Respect Movement, taking a more radical strand of the Dravidian movement, articulating the radical politics of caste and gender, and embarking on a far-reaching reform of Hindu society.

In her research article, *Advocacy journalism and the self-respect movement in late colonial South India*, published in *SudAsian-Chronik-South Asia Chronicle*, Uma Ganesan says *Kudi Arasu*, as a movement in itself, intervened in the crowded journalistic space of early 20th Century south India, which was dominated by Brahmins and other

upper-caste elites, to create an alternative space for articulating its goals and mobilising support for its programme of social reform. The movement, according to her, posed a radical challenge to the Gandhi-led Congress nationalism by identifying the Congress as a bastion of Hinduism and its caste system.

Justice Party's role

Author N.K. Mangalamurugesan, in his book, *Self-Respect Movement in Tamil Nadu 1920-1940*, wrote that the launching of the South Indian Liberal Federation (Justice Party) in 1916 marked the first step of non-Brahmins in challenging the Brahmin supremacy in the political and social fields.

"But the activities of the party were largely con-

finned to the interests of educated and rich non-Brahmins with the result that the bulk of the non-Brahmin masses remained untouched by them," he added.

Mangalamurugesan said the credit for making the non-Brahmin masses conscious of their rights goes to Periyar. "It is he who instilled into them a sense of pride and self-respect by starting the Self-Respect Movement," he said.

As a movement, it is known for its radical social reforms, including the introduction and popularisation of self-respect marriages, its advocacy for women's liberation from oppressive social norms like championing causes such as widow remarriage, the right to divorce, the right to property, abortion, among others.

प्रीलिम्स के लिए प्रमुख पहलू

1. **संस्थापक** – E.V. रामासामी "पेरियार" (1925, अपनी पत्रिका कुड़ी अरासुके माध्यम से)।
2. **मूल विचार** – कट्टरपंथी गैर-ब्राह्मणवाद, तर्कवाद, समानता, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक न्याय।
3. **संबद्ध सुधार** –
 - स्वाभिमान विवाह (पुजारियों या अनुष्ठानों के बिना, 1967 में तमिलनाडु में वैध)।
 - विधवा पुनर्विवाह, तलाक के अधिकार, विरासत के अधिकार, प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देना।
 - जाति-आधारित भेदभाव का उन्मूलन।
4. **जस्टिस पार्टी की भूमिका (1916)** - पहली गैर-ब्राह्मण राजनीतिक लामबंदी, लेकिन अभिजात वर्ग तक सीमित; पेरियार के आंदोलन ने इसे जन-जन तक पहुंचाया।
5. **पत्रकारीय भूमिका** – कुड़ी अरासु ने ब्राह्मण प्रधान प्रेस के खिलाफ एक वैकल्पिक मीडिया स्थान प्रदान किया।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता (GS I और II)

1. **समाज सुधार और जाति प्रश्न**

- आंदोलन ने जाति पदानुक्रम और ब्राह्मण प्रभुत्व पर हमला किया।
- पिछड़ी जातियों, दलितों और महिलाओं को संगठित किया और उन्हें सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदार बनाया।

2. महिला सशक्तिकरण

- अपने समय से बहुत पहले लैंगिक न्याय की वकालत की।
- विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति के अधिकार, प्रजनन अधिकार और दहेज के खिलाफ चैंपियन थे।

3. राजनीतिक महत्व

- द्रविड़ पार्टियों (जस्टिस पार्टी → द्रविड़कड़गम → डीएमके/एआईएडीएमके)केलिए वैचारिक आधार प्रदान किया।
- कांग्रेस के राष्ट्रवाद के खिलाफ एक जवाबी कथा बनाई, उस पर हिंदू रूढ़िवाद और जाति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

4. विरासत और प्रभाव

- क्षेत्रीय पहचान, तर्कवादी विचार और राज्य स्वायत्तता की बहस को मजबूत किया।
- तमिलनाडु में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसी नीतियों को प्रभावित किया।
- जाति और पितृसत्ता पर सवाल उठाना सामाजिक न्याय पर भारत में चल रही बहस के लिए प्रासंगिक है।

निष्कर्ष

आत्म-सम्मान आंदोलन केवल एक क्षेत्रीय सुधार नहीं था, बल्कि एक परिवर्तनकारी सामाजिक-राजनीतिक प्रयोग था जिसने तमिलनाडु के समाज और राजनीति को नया आकार दिया। तर्कवाद, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को अग्रभूमि देकर, इसने आरोपित पदानुक्रमों को चुनौती दी और हाशिए की आवाजों को सशक्त बनाया। एक सदी बाद, इसकी विरासत जाति, समानता और लोकतंत्र पर भारत के प्रवचन को आकार देना जारी रखती है – जिससे यह इतिहास और समकालीन शासन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन गया है।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: कुड़ीअरासु, आत्म-सम्मानआंदोलनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण पत्रिका, निम्नलिखित के लिए शुरू की गई थी:

- गांधी के अहिंसा और स्वदेशी विचारों को बढ़ावा देना
- साइमन कमीशन के खिलाफ समर्थन जुटाना
- जाति और लैंगिक सुधार की कट्टरपंथी राजनीति को मुखर करना
- ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का समर्थन करना

उत्तर : c)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: तमिलनाडु में जाति पदानुक्रम को चुनौती देने और तर्कवाद को बढ़ावा देने में आत्म-सम्मान आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन करें। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

गहरे अंतरिक्ष में नेविगेशन हमेशा इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। 2006 में लॉन्च किए गए नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने अब केवल दो निकटवर्ती सितारों – प्रॉक्सिमा सेंटॉरी और वुल्फ 359 का उपयोग करके आत्म-नेविगेशन की एक संभावित विधि का प्रदर्शन किया है। तारकीय लंबन पर आधारित यह तकनीक, भविष्य के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से स्वायत्तता प्रदान कर सकती है, जो लंबी अवधि के इंटरस्टेलर अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

Lost in space? You might need just two stars to find your way

As the earth orbits the sun, a star's position relative to other stars might seem to shift; this is called stellar parallax. This phenomenon happens because every six months, the earth is on opposite sides of the sun, providing two different viewpoints; you can achieve the same effect by looking at a candle with one eye at a time

Shreejaya Karantha

If you're lost somewhere on the earth, you can use GPS or public landmarks to find your way back. Navigation in the vastness of space isn't so easy, however – especially if you're on a spacecraft racing billions of kilometres away from the earth. There is no GPS in space, and where a landmark depends on where you're looking from. But recently, astronomers found that a deceptively simple trick could help the New Horizons spacecraft find its way through space using only two stars.

'Navigation is essential'

NASA launched New Horizons in 2006 to explore Pluto, its moons, and, later, objects in the Kuiper Belt, a disc of icy rocks and dust in the outer edge of the solar system. New Horizons flew by Pluto in 2015, beaming back stunning images of the dwarf planet and its moons. In 2024, the spacecraft went beyond 60x the sun-earth distance, a new record.

"Navigation is essential, just as it is on the earth," Max Planck Institute for Astronomy staff member Coryn Bailer-Jones said. "Spacecraft have to know where they are and where they are heading for many reasons" – from planning their fuel use to pointing their antennae to send data back home.

Interplanetary missions like New Horizons are tracked by NASA's Deep Space Network (DSN), a global array of giant radio antennae that send and receive signals from spacecraft. This system is precise but always earth-centred, i.e., the spacecraft's location is measured relative to our planet. As spacecraft travel farther, signals between ground stations and the spacecraft drop, increasing communication time and decreasing signal strength. Therefore spacecraft that can find their way without asking for directions from the earth will be at an advantage.

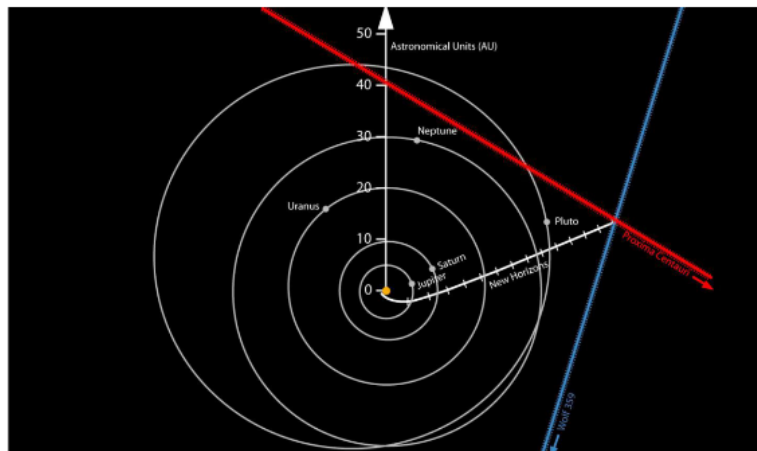
The new study proposes a simple way to do this using stellar parallax, the same method early astronomers used to measure stars' distances from the earth.

The findings were published in *The Astronomical Journal* in June.

One eye at a time

As the earth orbits the sun, a star's position relative to other stars might seem to shift. This is called stellar parallax.

This is because every six months, the earth is on opposite sides of the sun, providing two different viewpoints. You can achieve the same effect by looking at a candle first with only your left eye and then only your right eye: the candle will change position against the background. The amount of shift is called the



Location of New Horizons on April 23, 2020. The red and blue lines point to the locations of Proxima Centauri and Wolf 359 respectively. NEW HORIZONS/NASA

parallax angle, and it's directly related to the distance to the star.

In the study, the astronomers observed two stars from the earth using New Horizons' instruments. They're like two eyes that were 7 billion km apart on April 23, 2020, when the team made the observations.

The two stars were Proxima Centauri and Wolf 359, located 4.2 light years and 7.9 light-years away from the earth, respectively.

"We wanted large parallaxes, which means using the closest stars," U.S. National Science Foundation National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory astronomer and the study's lead author Tod Lauer said.

"Proxima Centauri is the closest star besides the sun. Wolf 359 is in the top five. We also needed stars that were not too bright for the camera. Wolf 359 was ... optimal for navigation, as it's close to 90° away from Proxima."

Self-sufficient

For the study's purposes, the European Space Agency's Gaia spacecraft played a vital role: it provided the 3D positions of stars in a fixed, universal reference frame.

With these reference positions, the team measured how much the stars' positions changed against the background by comparing their positions from New Horizons' vantage point with those from the earth.

The parallax was 32.4 arcseconds for Proxima and 15.7 arcseconds for Wolf 359



All it needs is a camera, a standard spacecraft computer, and a catalogue for reference positions on any spacecraft

TOD LAUER
U.S. NATIONAL SCIENCE FOUNDATION NATIONAL OPTICAL-INFRARED ASTRONOMY RESEARCH LABORATORY

at the time of measurement. (An arcsecond is equal to 1/3600th of a degree.)

This calculation indicated that New Horizons was positioned at 46.89-times the earth-sun distance – close to the 47.11 AU estimated by radio-tracking measurements from the earth.

The technique could be the simplest way to navigate spacecraft because it doesn't require special equipment, Mr. Lauer said.

"All it needs is a camera, a standard spacecraft computer, and a catalogue for reference positions on any spacecraft."

The team wrote in its paper that its demonstration was "educational," not yet ready for practical use.

"We can't improve [the accuracy] that much with New Horizons, but a better camera on another spacecraft would help," Mr. Lauer said.

Stars as compass

The "study is a good one and a nice demonstration," Mr. Bailer-Jones, who

wasn't involved in the study, said. "As they themselves note, it is not of practical use to navigate New Horizons, because we can still use earth-based beacons for this [distance]."

"But for much deeper space missions, such as interstellar travel, where beacons are no longer usable, an extension of this method becomes very useful."

He also said an existing method called stellar astrometric navigation also uses stars as well as accounts for the effects of special relativity to estimate a spacecraft's 3D position and velocity by measuring the angular separation between two stars in the sky. The new study has proposed a simpler version of this method, he added.

Mr. Bailer-Jones also said researchers are investigating another method called pulsar navigation, which uses rapidly spinning neutron stars like lamps in space to show the way.

"It's potentially much more accurate than stellar astrometric navigation, but it needs reasonable knowledge of the initial position, which the stellar astrometric navigation could supply," he said.

Mr. Lauer said he grew up watching *Star Trek* and that in one scene, he noticed the stars appeared to move as a spacecraft found its way through deep space. Did the show's producers know they were being accurate, or had they simply missed a detail? The new method has rendered this question irrelevant.

(Shreejaya Karantha is a freelance science writer. shreejayakaranth@gmail.com)

THE GIST

Interplanetary missions are monitored by radio antennae. This system is earth-centred. As spacecraft travel farther, communication time increases and signal strength decreases. Therefore, spacecraft need to navigate without asking for directions from the earth

The parallax was 32.4 arcseconds for Proxima Centauri and 15.7 for Wolf 359. This indicated that New Horizons was at 46.89-times the earth-sun distance – close to the 47.11 AU estimated by radio-tracking. This could be the simplest way to navigate spacecraft because it doesn't require special equipment

Scientists say the method is not of practical use to navigate New Horizons, because we can still use earth-based beacons for the distance involved. But for much deeper missions, such as interstellar travel, an extension of this method becomes very useful

प्रीलिम्स के लिए मुख्य अवधारणाएं

1. तारकीय लंबन

- पृष्ठभूमि के खिलाफ एक स्टार की स्थिति का स्पष्ट बदलाव जब दो अलग-अलग सहूलियत बिंदुओं से देखा जाता है।
- सितारों की दूरी मापने के लिए ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाता है; अब नेविगेशन के लिए पुनर्निर्मित किया गया।

2. प्रदर्शन

- न्यू होराइजन्स, पृथ्वी से ~ 47 एयू, प्रॉक्सिमा सेंटॉरी (4.2 प्रकाश वर्ष दूर) और वुल्फ 359 (7.9 प्रकाश वर्ष दूर) का अवलोकन किया।
- पृथ्वी और अंतरिक्ष यान से उनकी स्थिति की तुलना करके, खगोलविदों ने अच्छी सटीकता के साथ न्यू होराइजन्स की दूरी की गणना की।

3. सहायक मिशन

- गैया अंतरिक्ष यान (ईएसए): एक निश्चित संदर्भ फ्रेम में सितारों की सटीक 3 डी स्थिति प्रदान की।
- डीप स्पेस नेटवर्क (DSN): अंतरिक्ष यान के लिए वर्तमान पृथ्वी-आधारित रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम।

4. प्रमुखमाप

- प्रॉक्सिमा के लिए लंबन कोण: 32.4 आर्कसेकंड।
- वुल्फ 359 के लिए लंबन कोण: 15.7 आर्कसेकंड।
- अनुमानित स्थान: 46.89 एयू, पृथ्वी-आधारित ट्रैकिंग (47.11 एयू) के करीब।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

1. डीप-स्पेस नेविगेशन में चुनौतियां

- डीएसएन पृथ्वी-केंद्रित है, जो दूरी बढ़ने पर संचार देरी और कमजोर संकेतों को बढ़ाकर सीमित करता है।
- इंटरस्टेलर मिशन के लिए, पृथ्वी-आधारित ट्रैकिंग अव्यावहारिक हो सकती है।

2. प्रस्तावित समाधान

- तारकीय लंबन नेविगेशन - सरल, केवल एक कैमरा, कंप्यूटर और स्टार कैटलॉग की आवश्यकता होती है।
- तारकीय एस्ट्रोमेट्रिक नेविगेशन - अधिक उन्नत, सितारों के बीच सापेक्षता और कोणीय माप के लिए खातों।
- पल्सर नेविगेशन - प्राकृतिक बीकन के रूप में न्यूट्रॉन सितारों का उपयोग करता है; अधिक सटीक लेकिन प्रारंभिक स्थितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है।

3. लाभ

- आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान नेविगेशन।
- पृथ्वी स्टेशनों पर निर्भरता कम हो गई।
- भविष्य के इंटरस्टेलर मिशनों के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण।

4. सीमाओं

- वर्तमान प्रदर्शन "शैक्षिक" है और अभी तक व्यावहारिक रूप से पर्याप्त सटीक नहीं है।
- परिचालन उपयोग के लिए बेहतर उपकरणों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

न्यू होराइजन्स प्रयोग अंतरिक्ष में तारों को प्राकृतिक दिशासूचक के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना पर प्रकाश डालता है। हालाँकि पृथ्वी-आधारित प्रणालियाँ वर्तमान मिशनों के लिए विश्वसनीय बनी हुई हैं, लेकिन भविष्य में गहन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए स्वायत्त नेविगेशन विधियों की आवश्यकता होगी। तारकीय लंबन, तारकीय खगोलमिति और पल्सर नेविगेशन मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में अपने रास्ते खुद बना सकेंगे, जो अंतरतारकीय महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: न्यू होराइजन्स मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे नासा द्वारा मुख्य रूप से प्लूटो और कुइपर बेल्ट का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था।
2. इसने हाल ही में पास के सितारों का उपयोग करके अंतरिक्ष यान नेविगेशन की एक विधि का प्रदर्शन किया।
3. यह प्रॉक्सिमा सेंटॉरी और वुल्फ 359 के तारकीय लंबन को मापने के लिए उपकरणों से लैस है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर : d)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: न्यू होराइजन्स मिशन ने अंतरिक्ष यान नेविगेशन की एक विधि के रूप में तारकीय लंबन के उपयोग का प्रदर्शन किया। तारकीय लंबन के पीछे के सिद्धांत की व्याख्या करें और गंभीर रूप से विश्लेषण करें कि यह आत्मनिर्भर गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्राप्त करने में कैसे योगदान दे सकता है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

2023 नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रजनन दर में लगातार गिरावट और बुजुर्ग आबादी में वृद्धि के साथ भारत के चल रहे जनसांख्यिकीय संक्रमण की पुष्टि करती है। यह बदलाव, जबकि सामाजिक-आर्थिक प्रगति का एक मार्कर है, शासन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के लिए भविष्य की चुनौतियों का भी संकेत देता है।

प्रमुख प्रीलिम्स पॉइंटर्स

1. कूड जन्म दर (CBR)

- भारत (2023): प्रति 1,000 जनसंख्या पर 18.4 (2022 में 19.1 से नीचे)।
- उच्चतम: बिहार (25.8), सबसे कम: तमिलनाडु (12)।

2. कुल प्रजनन दर (TFR)

- भारत (2023): 1.9, प्रतिस्थापन स्तर से नीचे (2.1)।
- उच्चतम: बिहार (2.8)।
- निम्नतम: दिल्ली (1.2)।
- 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हैं।

3. वृद्ध जनसंख्या

- बुजुर्ग (60+ वर्ष): जनसंख्या का 9.7% (एक वर्ष में 0.7% की वृद्धि)।
- बुजुर्गों की उच्चतम हिस्सेदारी: केरल (15%)।
- सबसे कम: असम, दिल्ली, झारखंड।

4. जनसांख्यिकीय लाभांश

- भारत में अभी भी युवा कार्यबल है, लेकिन उम्र बढ़ने की प्रवृत्ति तेज हो रही है।

मुख्य प्रासंगिकता

1. गिरती प्रजनन क्षमता के निहितार्थ

- समय के साथ कार्यबल में गिरावट संभावित श्रम की कमी →।
- जापान, दक्षिण कोरिया, चीन की तरह आर्थिक मंदी का खतरा।

2. वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि

- स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे, जराचिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग।
- पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रणालियों पर तनाव।

Greying with grace

Changing population dynamics require a policy reorientation for governments

If there was any doubt about India going through the throes of a demographic change, confirmation came with the Sample Registration System (SRS) Statistical Report indicating a fall in the country's Crude Birth Rate (CBR) and Total Fertility Rate. As per the SRS data for 2023, India's CBR, defined as the number of annual live births in a population per 1,000 people, had declined to 18.4, a drop from 19.1 in 2022. The country's TFR had also fallen to 1.9, after hovering at 2.0 in 2021 and 2022. The TFR indicates the average number of children a woman will have in her lifetime to replace that generation, and a TFR of 2.1 births per woman is considered replacement-level fertility, translating to a stable population over time. Any figure over 2.1 suggests a growing population while rates below 2.1 signify a clear trend towards population decline and ageing. Of course, as usual, for a country of this size and diversity, there were vast regional differences. The highest CBR was in Bihar at 25.8, and the lowest was in Tamil Nadu at 12. Bihar also reported the highest TFR (2.8) and Delhi, the lowest (1.2). Eighteen States and Union Territories had a TFR below the replacement level, and all States reporting higher than replacement level TFR were in northern India – Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Chhattisgarh. Following Delhi, West Bengal, Tamil Nadu, and Maharashtra too have a TFR below 2.0. Simultaneously, as expected from such a demographic shift, SRS data indicated the proportion of people above 60 rose by 0.7 percentage points in a year to 9.7% of the population. Kerala has the highest proportion of elderly population, at 15%, while Assam, Delhi and Jharkhand reported the lowest proportion of their population over 60 years.

It will be foolhardy to look away from the writing on the wall. As the most populous nation, home to over 1.46 billion people, the current declining trend will admittedly take several years to have an impact on the population. However, there is no doubt that the nation, having, at least theoretically, prepared for 'more' all these years, should now prepare for a different future, while continuing to leverage the demographic dividend it still possesses thanks to a relatively young workforce. A greying nation will come with its own attendant concerns and needs – financial, universal access for reduced mobility, physical and mental health-care facilities and social support services. A 'young' nation, after all, will require a massive realignment to be ready to serve the needs of a growing population of the elderly.

- बुजुर्गों और अलग-अलग विकलांगों के अनुकूल शहरी डिजाइन और परिवहन प्रणालियों की आवश्यकता।

3. क्षेत्रीय असमानताएं

- उत्तर भारत (बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़) अभी भी प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता से ऊपर →।
- दक्षिण और पश्चिम भारत तेजी से बूढ़ा हो रहा → (केरल पहले से ही 15% बुजुर्ग)।
- नीति को दोनों चुनौतियों को संतुलित करना चाहिए: कुछ राज्यों में अधिक जनसंख्या बनाम दूसरों में उम्र बढ़ना।

4. नीति पुनर्विन्यास की आवश्यकता

- वृद्धावस्था देखभाल के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना।
- पेंशन, बीमा, बुजुर्गों के अनुकूल आवास जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करें।
- घटते कार्यबल को संतुलित करने के लिए महिला श्रम बल की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- उत्पादकता बनाए रखने के लिए कौशल विकास और स्वचालन में निवेश करें।
- वित्तीय स्वतंत्रता, गरिमा और सक्रिय उम्र बढ़ने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति 2.0 बनाएं।

निष्कर्ष

भारत एक जनसांख्यिकीय चौराहे पर खड़ा है। घटती प्रजनन दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के युग के अंत का संकेत देती है। जबकि जनसांख्यिकीय लाभांश अभी भी अवसर प्रदान करता है, नीति को एक धूसर समाज की तैयारी की दिशा में धुरी बनाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और कार्यबल प्रबंधन में सक्रिय सुधार यह निर्धारित करेंगे कि क्या भारत विकास और समावेशिता को बनाए रखते हुए गरिमापूर्ण तरीके से बूढ़ा हो सकता है।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: जनसांख्यिकीय अध्ययनों में, "रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी" को संदर्भित करता है:

- प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या को दोगुना करने के लिए आवश्यक प्रजनन दर
- समय के साथ स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रजनन दर
- विकसित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्रजनन दर
- वृद्ध जनसंख्या को युवा जनसंख्या से प्रतिस्थापित करने के लिए अपेक्षित प्रजनन दर

उत्तर : b)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत एक युवा राष्ट्र से एक वृद्ध समाज में जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इस बदलाव की क्षेत्रीय विविधताओं और सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा करें। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रस्तावित ₹ 72,000 करोड़ मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ने पर्यावरणीय स्थिरता, आदिवासी अधिकारों और आपदा तैयारियों पर गहन बहस शुरू कर दी है। जबकि सरकार इसे एक विकास पहल के रूप में पेश करती है, आलोचक इसकी गंभीर पारिस्थितिक और मानवीय लागतों को उजागर करते हैं, विशेष रूप से स्वदेशी जनजातियों और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के लिए।

The making of an ecological disaster in the Nicobar

There has been no shortage of half-baked and ill-conceived policymaking in the last 11 years. The latest in this series of planned misadventures is the Great Nicobar mega-infrastructure project. The totally misplaced ₹72,000 crore expenditure poses an existential danger to the island's indigenous tribal communities, threatens one of the world's most unique flora and fauna ecosystems, and is highly susceptible to natural disasters. Nevertheless, it is being insensitively pushed through, making a mockery of all legal and deliberative processes.

Uprooting tribals

The Great Nicobar Island is home to two indigenous communities, the Nicobarese tribe and the Shompen tribe (a Particularly Vulnerable Tribal Group). The ancestral villages of the Nicobarese tribals fall in the project's proposed land area. The Nicobarese were forced to evacuate their villages during the Indian Ocean tsunami of 2004. This project will now permanently displace this community, ending its dream of returning to its ancestral villages.

The Shompen face an even greater threat. The Island's Shompen Policy, notified by the Union Ministry of Tribal Affairs, specifically requires the authorities to prioritise the tribe's welfare and "integrity", when considering "large scale development proposals." Instead, the project denotifies a significant part of the Shompen tribal reserve, destroys the forest ecosystems where the Shompen live, and will cause a large-scale influx of people and tourists on the island. Ultimately, the Shompen will find themselves cut off from their ancestral lands and unable to sustain their social and economic existence. Yet, the Government is stubbornly adamant and shockingly insistent.

The Constitutional and statutory bodies set up to preserve tribal rights have been sidestepped throughout this process. As in Article 338-A of the Constitution, the Government should have consulted the National Commission for Scheduled Tribes. It has failed to do so. The Government should have consulted the Tribal Council of Great Nicobar and Little Nicobar Island. Instead, the Council Chairman's plea that the Nicobarese tribals be allowed to return to their ancestral villages has been neglected. A



Sonia Gandhi
is the Chairperson,
Congress
Parliamentary Party

Letter of No Objection was secured from the Council, but it has since been revoked, with the Council noting that the authorities had "rushed them" into signing the letter.

Due process and regulatory safeguards set up to protect local communities have been evaded. The Social Impact Assessment (SIA) conducted as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 should have considered the Nicobarese and Shompen as stakeholders of the process and evaluated the project's impact on them. Instead, it omits any reference to them altogether. The Forest Rights Act (2006), which empowers the Shompen as the authority to protect, preserve, regulate and manage the forests, should have underpinned any policy action. Instead, the Shompen have not been consulted on this issue – a fact which the Tribal Council has now confirmed. The country's laws are being mocked wholesale. Unconscionably, one of the country's most vulnerable groups may have to pay the ultimate price for it.

The farce of compensatory afforestation

Ecologically, this project is nothing short of an environmental and humanitarian catastrophe. The project will require the cutting down of trees on an estimated 15% of the island's land, decimating a nationally and globally unique rainforest ecosystem. The Ministry of Environment, Forests, and Climate Change estimates that 8.5 lakh trees may be cut. This is a depressing figure, but it may also be a gross underestimate – independent estimates have suggested that 32 lakh trees to 58 lakh trees may eventually be cut.

The Government's solution to this indiscriminate tree felling is that of 'compensatory afforestation', a rather poor substitute for the loss of natural, old-growth forests. Inexplicably, the planned afforestation is in Haryana, a State that is thousands of kilometres away, and in a decidedly different ecology. In a tragedy bordering on farce, a quarter of this land planned for afforestation has now been auctioned off by the Haryana Government for mining. In any case, compensatory afforestation may help assuage a guilty conscience but is simply no substitute for

the destruction of multi-species, biodiversity-rich natural forests. The planned port site is also controversial with some of it falling under the Coastal Regulation Zone (CRZ) IA. Port construction is prohibited in CRZ IA areas due to the presence of turtle nesting sites and coral reefs.

Despite abundant evidence confirming the same, which includes a National Green Tribunal order, the Government has contrived ways to manipulate this truth through a high-powered committee (HPC). The report of this HPC and the ground-truthing exercise it conducted to reclassify the port site out of CRZ IA has not been made public.

Flaws in methodology

From a wildlife standpoint too, the project raises serious concerns. Primatologists have written to the Government expressing grave concerns about the project's impact on the Nicobar long-tailed macaque. These concerns have been ignored. The biodiversity assessments for the projects have come under questioning for critical methodological flaws. The assessment of sea turtle nesting sites was conducted in the off-season for nesting. Drones were employed to gauge the project's impact on dugongs, but these drones have limited capacity and can only assess shallow areas. Evidence has emerged that the institutes were made to conduct these assessments under highly unusual conditions, bordering on duress.

Finally, the project – including the port – is coming up in a seismically sensitive earthquake prone zone. The tsunami of December 2004 saw a permanent land subsidence of about 15 feet. The 6.2 magnitude earthquake in the Andaman and Nicobar Islands in July 2025 only reminds us of this ever-present threat. Locating such a massive project here deliberately jeopardises investment, infrastructure, people, and the ecology.

Our collective conscience cannot, and must not, stay silent when the very survival of the Shompen and Nicobarese tribes is at stake. Our commitment to future generations cannot permit this large-scale destruction of a most unique ecosystem. We must raise our voice against this travesty of justice and this betrayal of our national values.

The Great Nicobar Island Project is a grave misadventure, trampling on tribal rights and making a mockery of legal and deliberative processes

प्रमुख प्रीलिम्स पॉइंट्स

1. ग्रेट निकोबार द्वीप जनजाति

- निकोबारी (अनुसूचित जनजाति)।
- शोम्पेन (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह - PVTG)।

2. प्रासंगिक कानून और सुरक्षा उपाय

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 → आदिवासी समुदायों को वनों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार → सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता है।
- अनुच्छेद 338क → राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अवश्य परामर्श किया जाना चाहिए।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) 1A → कछुए के घोंसले और प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में बंदरगाह निर्माण को प्रतिबंधित करता है।

3. पारिस्थितिक प्रभाव

- अनुमान है कि 8.5 लाख से 58 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं।
- वर्षावनों का नुकसान, कछुए के घोंसले के मैदान, प्रवाल भित्तियाँ, दुर्गोंग आवास, निकोबार मकाक।
- हरियाणा में प्रतिपूरक वनीकरण की योजना (पारिस्थितिक रूप से अप्रासंगिक)।

4. आपदा जोखिम

- भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र - 2004 सुनामी (भूमि उप-विभाजन ~ 15 फीट) देखा।
- जुलाई 2025 भूकंप (6.2 परिमाण) भेद्यता पर प्रकाश डालता है।

मुख्य प्रासंगिकता

1. जनजातीय समुदायों पर प्रभाव

- निकोबारी का स्थायी विस्थापन (2004 की सुनामी से पहले से ही प्रभावित)।
- वन आवास के नुकसान के कारण शोम्पेन जनजाति के अस्तित्व के लिए खतरा।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन।

2. शासन और कानूनी मुद्दे

- NCST और जनजातीय परिषदों को दरकिनार करना।
- जनजातियों को छोड़कर सामाजिक प्रभाव आकलन।
- संदिग्ध पर्यावरणीय मंजूरी और अपारदर्शी एचपीसी रिपोर्ट।

3. पारिस्थितिक और जैव विविधता हानि

- "पुराने-विकास वाले उष्णकटिबंधीय वर्षावन का अपरिवर्तनीय विनाश"।
- स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरा।
- द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र से दूर गलत वनीकरण के प्रयास।

4. आपदा प्रबंधन संबंधी चिंताएं

- सुनामी प्रवण और भूकंप-प्रवण क्षेत्र में स्थित परियोजना।
- बुनियादी ढांचे, निवेश और जीवन के लिए उच्च जोखिम।

5. नैतिक और विकासात्मक दुविधा

- सतत विकास बनाम पारिस्थितिक न्याय पर सवाल उठाता है।
- अल्पकालिक आर्थिक लाभ के खिलाफ स्वदेशी अस्तित्व और पारिस्थितिक सुरक्षा रखता है।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना पारिस्थितिक और सामाजिक संवेदनशीलता के बिना विकास को आगे बढ़ाने के जोखिमों का उदाहरण है। आदिवासी अधिकारों को कम करके, पर्यावरण सुरक्षा उपायों की अनदेखी करके, और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को भूकंपीय रूप से नाजुक क्षेत्र में धकेलकर, यह एक पारिस्थितिक और मानवीय आपदा बनने का जोखिम उठाता है। सच्ची प्रगति के लिए पर्यावरणीय स्थिरता, आपदा लचीलापन और स्वदेशी समुदायों की गरिमा के साथ राष्ट्रीय विकास को संतुलित करने की आवश्यकता है।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: ग्रेट निकोबार द्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक विशेषताएं मौजूद हैं?

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. प्रवाल भित्तियाँ | 2. समुद्री कछुए के घोंसले के शिकार स्थल |
| 3. उष्णकटिबंधीय वर्षावन | 4. दुर्गोंग निवास स्थान |

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

- | | |
|--------------------|------------------|
| (a) केवल 1, 2 और 3 | (b) केवल 2 और 4 |
| (c) केवल 1, 3 और 4 | (d) 1, 2, 3 और 4 |

उत्तर: d)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2004 की सुनामी और 2025 के भूकंप के विशेष संदर्भ में, पारिस्थितिक रूप से नाजुक और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रखने के आपदा जोखिमों का मूल्यांकन करें। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Page : 09 Editorial Analysis

GST 2.0 will empower young Indians

India's greatest strength is its people. With nearly two-thirds of the population under the age of 35 years, the country's economic engine is powered by aspiration, enterprise and consumption. This demographic dividend is not merely a statistic. It is the pulse of an economy that is increasingly youthful, ambitious and globally connected. GST 2.0 is a reform that directly responds to this advantage. By simplifying rates, reducing burdens on essentials and exempting services such as insurance, the new structure of GST 2.0 strengthens household purchasing power and supports the ambitions of young India.

India's household spending

Private consumption already accounts for over 60% of India's GDP, a proportion far higher than in many other large economies. This makes household spending the single-most powerful driver of national growth. When families save on taxes, even by a small margin, their disposable income increases. Multiplied across millions of households, these savings translate into significant demand for goods and services—from basic necessities to education, health care, housing and digital products. GST 2.0 unleashes this multiplier effect, ensuring that affordability at the micro-level translates into growth at the macro-level.

For young households balancing equated monthly instalments (EMI), health-care expenses and education costs, the reform provides genuine relief. Reduced taxes on essentials ease monthly financial pressure, while exemptions on critical services such as insurance encourage a culture of protection and planning. For many families in urban and semi-urban areas, the reform could be the difference between postponing an aspiration and achieving it sooner. By making everyday life slightly more affordable, GST 2.0 makes long-term goals such as home



Suneeta Reddy
is Managing Director
of Apollo Hospitals
Enterprise Limited

The reform will align fiscal policy with the aspirations of a young population

ownership, education or health security more attainable.

The exemption of GST on health and life insurance premiums is particularly meaningful. India's insurance penetration has historically been low, and cost has been a major barrier. For a young workforce juggling EMIs, student loans and discretionary spending, insurance often felt like an avoidable burden. Removing the tax burden changes that equation. It sends a clear message that financial protection is not just an individual choice but a national priority. Over time, this measure will accelerate insurance penetration, strengthen household resilience and reduce the vulnerability of families to sudden medical or financial shocks. In the process, it creates a healthier, more secure society—one where risk is shared, not borne by individuals alone.

The reform is equally significant for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), which together employ over 110 million people and contribute substantially to India's GDP. For decades, compliance complexities and uneven tax structures have discouraged many small firms from formalising. GST 2.0 simplifies these processes, reducing friction and encouraging wider participation in the formal economy. For young entrepreneurs, this translates into easier access to credit, greater visibility in supply chains and stronger confidence in building businesses that can scale. By easing the path for MSMEs, the reform empowers the very segment that provides jobs and opportunities to young India.

Youth-driven consumption creates a virtuous cycle. When affordability increases, demand rises. Rising demand encourages new investments. Investments generate employment. Employment fuels further consumption. This cycle, once strengthened, becomes self-sustaining. GST 2.0 nurtures this cycle by aligning fiscal policy

with the realities of a youthful and ambitious nation. It recognises that consumption is not merely a private activity but the collective force that shapes the country's growth trajectory.

Just as important as affordability is predictability. A tax system that is transparent, consistent, and stable provides confidence to young professionals planning their financial futures. Entrepreneurs too benefit from knowing that their compliance costs will not fluctuate unpredictably.

GST 2.0, with its two-tier structure, addresses this need for predictability. It reassures citizens that India's economic journey will be supported by fair and transparent governance. That trust is as important as the immediate financial relief delivered by lower rates.

Few countries have enjoyed a demographic opportunity on the scale that India does today. But such advantages can also become risks if not properly harnessed. A young population without opportunities can quickly turn disillusioned. GST 2.0 is a step toward ensuring that India's youth dividend is not squandered. By aligning fiscal reform with the aspirations of a young population, it creates the conditions for inclusive, consumption-led and sustainable growth.

A new foundation

As India moves towards becoming a mature, consumption-driven economy, GST 2.0 provides the fiscal architecture to channel youthful aspiration into national momentum. It is a reform that reduces financial barriers, encourages protection, supports entrepreneurs and builds trust. Most importantly, it is not only a reform for today's households but also a foundation for the India that this generation will build. By empowering young India to spend, save, and secure its future, GST 2.0 strengthens the very core of the country's economic promise.

जी एस। पेपर 02 और 03 – सामाजिक न्याय और भारतीय अर्थव्यवस्था

UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न: आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये कि GST 2.0 भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने में कैसे मदद कर सकता है। उन चुनौतियों पर चर्चा करें जो युवाओं के नेतृत्व वाली खपत और उद्यमिता पर इसके प्रभाव को सीमित कर सकती हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

संदर्भ:

भारत, जिसकी लगभग दो-तिहाई आबादी 35 वर्ष से कम है, एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करता है। जीएसटी 2.0 की शुरुआत, जिसका उद्देश्य दरों को सरल बनाना, आवश्यक वस्तुओं पर बोझ कम करना और बीमा जैसी सेवाओं को छूट देना है, इस युवा लाभ का दोहन करना चाहता है। परिवारों और व्यवसायों पर वित्तीय दबाव को कम करके, सुधार समावेशी, उपभोग आधारित विकास के चालक के रूप में तैनात है।

प्रमुख प्रीलिम्स पॉइंट्स

1. घरेलू उपभोग

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 60% से अधिक है।
- जीएसटी 2.0 आवश्यक वस्तुओं पर करों को कम करता है → उच्च डिस्पोजेबल आय को कम करता है।

2. छूट

- स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम छूट → बीमा पैठ और वित्तीय लचीलापन को बढ़ाता है।
- ईएमआई, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल लागत का प्रबंधन करने वाले युवा परिवारों का समर्थन करता है।

3. एमएसएमई पर प्रभाव

- भारत के एमएसएमई 110+ मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं।
- सरलीकृत अनुपालन → औपचारिकता, क्रेडिट तक पहुंच और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।

4. दो स्तरीय जीएसटी संरचना

- कराधान में पूर्वानुमेयता, पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

मुख्य प्रासंगिकता

1. जनसांख्यिकीय लाभांश और खपत-आधारित विकास

- युवा-संचालित खर्च एक पुण्य चक्र बनाता है: उपभोग → निवेश → रोजगार → अधिक खपत।
- जीएसटी 2.0 कर बाधाओं को कम करके और आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके इस चक्र को मजबूत करता है।

2. वित्तीय समावेशन और घरेलू लचीलापन

- बीमा प्रीमियम में छूट देने से चिकित्सा या वित्तीय झटके की भेद्यता कम हो जाती है।
- जोखिम-साझाकरण और वित्तीय नियोजन की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।

3. एमएसएमई सशक्तिकरण और औपचारिक अर्थव्यवस्था

- सरलीकृत अनुपालन छोटे व्यवसायों के लिए बाधाओं को कम करता है।
- औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक भागीदारी → बेहतर क्रेडिट पहुंच और रोजगार सृजन में सुधार हुआ।

4. नीति पूर्वानुमेयता और आर्थिक विश्वास

- पारदर्शी, स्थिर कराधान युवा पेशेवरों और उद्यमियों के बीच विश्वास पैदा करता है।
- राजकोषीय नीति को दीर्घकालिक आर्थिक नियोजन के साथ संरेखित करता है।

5. समावेशी और सतत विकास

- युवाओं की आकांक्षाओं को दिशा देकर, जीएसटी 2.0 परिवारों और उद्यमों में समान लाभ सुनिश्चित करता है।
- वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देता है।

निष्कर्ष

जीएसटी 2.0 एक राजकोषीय सुधार से अधिक है; यह भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए एक रणनीतिक उपकरण है। कर के बोझ को कम करके, घरेलू डिस्पोजेबल आय को बढ़ाकर, एमएसएमई का समर्थन करके और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करके, यह युवा भारत की महत्वाकांक्षाओं के साथ नीति को संरेखित करता है। सुधार न केवल उपभोग आधारित विकास को मजबूत करता है, बल्कि स्थायी, समावेशी आर्थिक विकास की नींव भी रखता है, अगली पीढ़ी को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और राष्ट्रीय प्रगति को चलाने के लिए सशक्त बनाता है।